i Next 24-01-2018

3.25 करोड़ से बनेगा हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर

KANPUR (23 Jan): नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट शुगर इंडस्ट्री के लिए लगातार अच्छा काम कर रहा है. संस्थान के रिसर्च वर्क से शुगर इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है. अब शुगर इंडस्ट्रीज को इस संस्थान से हाथ मिलाकर रिसर्च वर्क कराना चाहिए. ये बातें एनएसआई में डेवलप ईस्ट (माइक्रो आर्गेनिज्म शुगर को एल्कोहल में कनवर्ट करता है) को लॉन्च करते हुए फूड सेक्रेट्री रविकांत कहीं. अभी तक देश की शुगर इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनियों के ईस्ट का यूज करती थीं. जबकि एनएसआई में तैयार ईस्ट की क्वालिटी बाहरी कंपनियों से बेहतर है. यहां फूड सेक्रेट्री व ज्वाइंट सेक्रेट्री सुभाष पांडा ने डायरेक्टर एनएसआई प्रो नरेन्द्र मोहन के साथ 9 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया. जिसमें आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर व हॉस्टल के साथ गेस्ट हाउस शामिल है. वहीं संस्थान को रिफाइंड शुगर बनाने की लैब डेवलप करने पर फूड सेक्रेट्री ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है. यहां प्रो आशुतोष बाजपेई, प्रो संतोष कुमार, प्रो सीमा परोहा,जितेन्द्र सिंह शिखा सिंह, अनुष्का अग्रवाल मौजूद रहीं.

PIC. DAINIK JAGRAN I NEXT

प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते चीफ गेस्ट.

हिन्दुस्तान 24-01-2018

एनएसआई में सचिव और संयुक्त सचिव ने रखी आधार शिला

₹ 8.95 करोड़ से बनेगा ट्रेनिंग सेंटर और हॉस्टल

शर्करा संस्थान

कानपुर | कार्यालय संवाददाता

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) में भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव रविकांत ने मंगलवार को 8.95 करोड़ रुपये के बजट से प्रशिक्षण केंद्र और छात्रावास सह अतिथि गृह की आधारशिला रखी।

इसमें 3.25 करोड़ रुपये से प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होगा। इसमें 200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। 5.70 करोड़ से छात्रावास सह अतिथि गृह बनेगा। छात्रावास का निर्माण सत्र 2017-18 से शुरू हो रहे नए कोर्स गुणवत्ता प्रबंधन व पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा को ध्यान में रख किया जाएगा।

सचिव रविकांत, संयुक्त सचिव (शर्करा एवं प्रशासन) सुभाशीष पांडा के साथ पहुंचे। उन्होंने निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन के साथ पहले इन दो बड़ी योजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद संस्थान का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला पहुंचे, जिसे हाल में ही एनबीएल मान्यता मिली है। यह प्रयोगशाला उच्चतर विश्लेषण करके राजस्व भी कमा सकेगी। इसके बाद उन्होंने स्मार्ट कक्षा, प्रेक्षागृह का नवीनीकरण, प्रयोगशाला, स्टेट बैंक की सहायत से निर्मित एटीएम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।

मंगलवार को एनएसआई में योजनाओं की आधारशिला रखते सचिव रविकांत, संयुक्त सचिव सुभाशीष पांडा और निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन। ● हिन्दुस्तान

लाभ के लिए चीनी मिलें करें अन्य प्रयोग : सचिव रविकांत ने संस्थान में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए नवनिर्मित नैनो एथनॉल इकाई व शराब भट्टी का भी दौरा किया। विभिन्न अनुसंधानों जैसे बगास से जैव डिटर्जेंट का उत्पादन, बगास से खाद्य मशरूम, शर्करा उद्योग के प्रेस मड व अन्य वेस्ट से बायो सीएनजी का उत्पादन, विद्युत स्कंदन तकनीक द्वारा अवशिष्ट जल का प्रबंधन आदि की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को लाभ लेने के लिए ऐसे प्रयोग करने चाहिए।

जल्द भरें जाएंगे रिक्तपद : प्रो. नरेंद्र मोहन ने सचिव को बताया कि संस्थान में करीब 307 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में सिर्फ 142 पद ही भरे हैं। सचिव ने इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

शुरू होगा आसवनी तकनीक पाठ्यक्रम : निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि जल्द एक और नया कोर्स आसवनी तकनीक की भी शुरुआत की जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र बनने से संस्थान में सेमिनार, संगोष्ठियां हो सकेंगी।

पायनियर 24-01-2018

शर्करा संस्थान में खाद्य सचिव ने किया दौरा, रखी आधारशिलाएं

● रखी गयी प्रशिक्षण केंद्र, छात्रावास और सह अतिथि गृह के निर्माण की आधारशिला

पायनियर समाचार सेवा। कानपुर

नारामऊ स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में आज खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव आईएएस.रविकांत ने दौरा किया और संस्थान के अनुसंधान, शैक्षिक व अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। सुभासिश पंडा, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव, (शर्करा एवं प्रशासन), भारत सरकार उनके साथ थे। संस्थान के परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र एवं छात्रावास सह अतिथि गृह के निर्माण की आधारशिला रखी। प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण अनुमानित राशि रू0 3.25 करोड़ में होना है एवं इसमें 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। यह प्रशिक्षण केन्द्र नवीनतम प्रभावी अध्यापन व प्रशिक्षण के लिए श्रव्य/दृश्य से सुसज्जित होगा।

जानकारी देते हुए संस्थान निदेशक प्रो. नरेन्द्र मोहन, ने बताया कि लम्बे समय से इस प्रशिक्षण केन्द्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि संस्थान कई सेमिनार, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ भी शामिल है। प्रस्तावित छात्रावास में 48 विद्यार्थियों-प्रशिक्षुओं के रहने की व्यवस्था है एवं इसमें शैक्षिक सत्र 2017-18 से शुरू हो रहे नये कोर्स 'गुणवत्ता प्रबन्धन व पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। संस्थान द्वारा भविष्य में एक नया कोर्स 'आसवनी तकनीक' का भी आरम्भ किया जाएगा। छात्रावास का निर्माण अनुमानित राशि 5.70 करोड़ में होना है। रविकान्त, आईएएस, सचिव, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण), सुभासिश पंडा, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव, (शर्करा एवं प्रशासन) ने संस्थान की 'राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला' का दौरा किया, जिसे हाल में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हुई है। एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्ति के बाद, संस्थान शर्करा व अन्य प्रतिरूपों के लिए उच्चतर विश्लेषण करके ज्यादा राजस्व कमा सकेगा। उन्होंने संस्थान में जारी

छात्रावास और अतिथि गृह की आधारशिला रखते आईएएस. सचिव रविकांत व निदेशक संस्थान प्रो.नरेन्द्र मोहन पायनियर

विभिन्न दूसरी गतिविधियों जैसे-मौजूदा कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में बदलना, प्रेक्षागृह का नवीनीकरण, संशोधित विभिन्न प्रयोगशाला एवं स्टेट बैंक की सहायता से निर्मित ए.टी.एम. का भी निरीक्षण किया एवं उन्होंने इन कार्यों पर अपनी सन्तुष्टि प्रकट की। उन्होंने विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए नवनिर्मित 'नैनो एथनॉल इकाई व शराब भट्टी' का भी दौरा किया। इसके बाद रविकांत, आईएएस, सचिव, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) ने विभिन्न प्रयोगशालाओं का दौरा किया एवं इनमें जारी अनुसंधान व विकास कार्यों को देखा। संस्थान में जारी नवीनतम अनुसंधान कार्य जैसे-बगास से जैव डिटरजेन्ट का उत्पादन, बगास से खाद्य मशरूम, शर्करा उद्योग के प्रेस मड व अन्य अवशिष्ट पदार्थों से जैव सीएनजी का उत्पादन की भी समीक्षा की। उन्होंने संस्थान द्वारा जारी अनुसंधान कार्य 'विद्युत स्कन्दन तकनीक द्वारा अवशिष्ट जल का प्रबन्धन', पर संस्थान की प्रशंसा की। उन्होंने इन सभी तकनीकों को प्रयोगशाला से व्यावहारिक प्रयोग व वाणिज्यिक उपभोग में लाने की सलाह दी। उन्होंने संस्थान द्वारा शीरा आधारित शराब भट्टी के लिए विकसित 'एन.एस.आई./बीसी/114, खमीर स्ट्रेन' को विक्री के लिए जारी किया। यह स्ट्रेन खराब गन्ना जूस से प्राप्त किया जाता है एवं शराब उत्पादन के लिए शर्करा को शीरा में बदलता है। खमीर स्ट्रेन की किण्वन क्षमता पहले ही पॉयलेट स्केल परीक्षणों व प्रयोगशालाओं में जाँची जा चुकी है एवं इसे मौजूदा सभी वाणिज्य स्ट्रेनों से बेहतर पाया गया। निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने बताया कि हम पहले ही कई शराब भटिट्यों से इसके खरीद के बारे में पूछ-ताँछ कर चुके हैं। उन्होंने संस्थान के विभिन्न मामलों विशेषकर रिक्त पदों (स्वीकृत पद 307, भरे हुए पद 142) को भी देखा एवं इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही का आश्वासन दिया।

दैनिक जागरण 24-01-2018

होगा लाभ तबादला होने के बाद कार्डधारकों को नहीं होना होगा परेशान, तेलंगाना व ओडिशा के बाद यूपी में भी ऑनलाइन होने जा रही व्यवस्था

किसी भी शहर में खाद्यान्न ले सकेंगे राशनकार्ड धारक

जागरण संवाददाता, कानपुर : देशभर की सरकारी दुकानों के लिए अब एक ही राशनकार्ड होगा। देश के किसी भी शहर में स्थानांतरण होने पर वही कार्ड काम करेगा जो आपके पास है। तेलंगाना व ओडिशा के बाद देशभर में राशनकार्ड ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था जल्द लागू होने की संभावना है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। यह जानकारी विभाग के सचिव रविकांत ने दी। वह मंगलवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे।

संस्थान के छात्रावास सह अतिथि गृह व प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखने के लिए बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने आए रविकांत ने बताया कि देशभर में 80 फीसद राशनकार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है। सभी राशनकार्ड धारकों का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। इससे सभी लोगों को राशनकार्ड के जरिए अनाज मिलने के साथ राशनकार्ड के फर्जीवाड़े पर भी शिकंजा कसेगा वहीं देशभर की

लोकार्पण करते खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव रविकांत व साथ में शर्करा एवं प्रशासन के संयुक्त सचिव सुभाशीष पन्डा व एनएसआइ निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ● जागरण

किसी भी सरकारी राशन की दुकान पर अनाज लेने के दौरान उपभोक्ताओं को बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस मशीन की व्यवस्था सभी दुकानों पर की जा रही है। भविष्य में सभी राशनकार्ड ऑनलाइन होने के कारण उपभोक्ताओं का तुरंत सत्यापित करके उन्हें अनाज मुहैया कराया जाएगा।

एक तारीख से बंटना शुरू हो जाएगा खाद्यान्न : समय पर उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न वितरित कराने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग नई व्यवस्था करने जा रहा है। गोदाम से खाद्यान्न उठाने के झंझट से दुकानदार दूर रहेंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह गोदामों से उठाकर दुकानों पर 30 तारीख तक खाद्यान्न पहुंचाए, तभी एक तारीख से इसका वितरण शुरू होगा। अभी कई दुकानों में खाद्यान्न वितरण की शुरुआत 15 से लेकर 20 तारीख तक हो पाती है। राशन लेने के लिए उपभोक्ताओं के संदेश आएगा। जबकि राशन दुकानदार का कमीशन बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

● आधार से लिंक हो रहे राशनकार्ड पकड़ा जाएगा फर्जीवाड़ा

इंडस्ट्री तक पहुंचे छात्रों की रिसर्च

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शर्करा एवं प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव शुभाशीष पंडा ने बताया कि इंडस्ट्री तक छात्रों की रिसर्च पहुंचाई जाएगी। इसमें बगास से जैव डिटरजेंट का उत्पादन, बगास से खाद, शर्करा उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन मुख्य रूप से शामिल हैं। इंडस्ट्री को इन शोध कार्यों को अपनाकर इसका लाभ उठाना चाहिए।

3.25 करोड़ में प्रशिक्षण केंद्र व 5.70 करोड़ में बनेगा छात्रावास : एसआई में 3.25 की लागत से प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होगा। इसमें दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी जबकि यहां ऑडियो वीडियो लैब भी स्थापित की जाएगी। जहां छात्र डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। एनएसआइ निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि इसके अलावा यहां 5.70 करोड़ में छात्रावास बनेगा जिसमें 48 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा नए शुरू हुए 'गुणवत्ता प्रबन्धन व पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' कोर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण कराया जा रहा है। इस साल से एक और नया कोर्स 'आसवनी तकनीक' भी शुरू होगा। इस दौरान प्रो. नरेंद्र मोहन ने सचिव रविकांत से संस्थान में स्वीकृत 307 पद के सापेक्ष 142 पद भरे होने के बारे में भी बताया। इस पर सचिव ने पद भरने की दिशा में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

The Pioneer 24-01-2018

Foundation-stone of training centre building laid at NSI

PIONEER NEWS SERVICE KANPUR

Secretary, Food and Public Distribution, Ravikant visited National Sugar Institute on Tuesday to review the research, academic and other activities

He laid the foundation-stone for construction of training centre and hostel-cum-guest house. The training centre will be constructed at an estimated cost of ₹3.25 crore and will have a seating capacity for 200 persons and will be equipped with the latest audio visual aids for effective teaching and training.

The Director, Prof Narendra Mohan said the need was long felt and the proposed hostel will accommodate 48 students and was very much required keeping in view commencement of a new course PG diploma in Quality Control and Environment Science from the academic session 2018-19 and one more course on 'Wine brewing technology' in future. He said the hostel will also have stay facility for the visitors, experts and dignitaries visiting the institute. He said the hostel was being constructed at an estimated cost of ₹ 5.75 crore. He said the NSI Analytical Laboratory has recieved NABL recently. He said with such an accreditation the institute will be able to earn higher revenue by carrying out analysis of sugar and other samples. The dignitaries also looked into various other on going activities like conversion of existing classrooms into Smart Classrooms, renovation of auditorium, modification activities in various laboratories and construction of an ATM with the help of SBI

Later on Ravikant visited various laboratories to see the ongoing research and development work. He showed keen interest in the innovative work being carried out by the institute on production of biodetergents and bagasse. He also viewed other issues and sanctioned a strength of 307 only 142 posts were filled up on priority.

My City 24-01-2018

एनएसआई में हॉस्टल, ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास

हॉस्टल, ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करते सचिव खाद्य एवं वितरण रमाकांत, साथ में एनएसआई के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन। अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर।

नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) में मंगलवार को 50 छात्रों के छात्रावास और दो सौ लोगों की क्षमता वाले ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी गई। मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण रविकांत और संयुक्त सचिव (शर्करा एवं प्रशासन) सुभाशीष पांडा रहे।

हॉस्टल में छह वीआईपी कमरे भी होंगे जो वीआईपी गेस्ट हाउस के रूप में काम आएंगे। इसमें 25 डबल बेड वाले कमरे भी होंगे। यह 3.25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा। इसके अलावा 5.75 करोड़ रुपये की लागत से एक ट्रेनिंग सेंटर की तैयार बनाया जाएगा। जिसकी क्षमता दो सौ की है। यह दोनों काम अगले साल जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। दोनों सचिव ने संस्थान में चल रहे शोध कार्यों की काफी सराहना की। इस दौरान संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन सहित कई अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

यीस्ट स्ट्रेन की हुई लांचिंग

अतिथियों ने एनएसआई के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई यीस्ट स्ट्रेन की लांचिंग भी की। यह एक ऐसी तकनीक है जो एल्कोहल बनाने वाली यूनिट में काम आता है। इसकी मदद से सड़े गन्ने के रस के जरिए एल्कोहल बनाया जाएगा। इसे एल्कोहल बनाने वाली कंपनियां एनएसआई से साढ़े बारह हजार रुपये प्रति प्लांट की कीमत से खरीद सकते हैं।

भरे जाएंगे रिक्त पद

एनएसआई के रिक्त पदों को भी सचिव ने भरने के लिए आश्वासन दिया। संस्थान में कुल 307 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 142 भरे हुए हैं। शेष पद रिक्त चल रहे हैं। इसके लिए सचिव ने कहा कि वह जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। दोनों सचिव ने संस्थान परिसर का निरीक्षण भी किया और संस्थान में चल रहे शोध कार्यों का जायजा लिया।

शुरु होगा नया डिप्लोमा कोर्स

एनएसआईटी में अगले सत्र से गुणवत्ता प्रबंधन व पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जाएगी। इसमें 15 सीटें होंगी। एनएसआई के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि जल्द ही इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आज 24-01-2018

अब किसी भी कोटेदार से ले सकेंगे राशन

आंध्रप्रदेश, तेलंगाना व उड़ीसा में लागू है नई व्यवस्था ,राशन डीलरों की दुकानों पर राशन पहुंचायेंगी सरकार

कानपुर, 23 जनवरी। खाद एवं सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार केंद्रीय सचिव रविकांत ने कहाकि अब देशभर के राशन डीलरों और राशन कार्डों को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है जिसके चलते अब उपभोक्ता कही भी राशन डीलर से अपना राशन ले सकेगा। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सभी डीलरों के यहां पीएसओ मशीन लगाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों में ये नयी व्यवस्था लागू कर दी गयी है और वहां फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगने के साथ बेहतर नजीते भी मिल रहे हैं। वह आज राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में प्रशिक्षण केंद्र, छात्रावास व सह अतिथि गृह का शिलान्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

छात्रावास का शिलान्यास करते सचिव रविकांत, निदेशक नरेन्द्र मोहन।

सचिव ने बताया कि खाद्य वितरण में लीकेज बंद कर सभी राशन डीलरों को डिजिटलाइजेशन पर जोर है और राशन कार्डों के साथ आधार को लिंक किया जा रहा है। ये कार्य पूरा होने पर अब किसी भी डीलरों से कोई उपभोक्ता राशन ले सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत चल रही और सभी डीलरों को पीएसओ मशीन लगाने पर जोर है। अब अप्रैल 2018 से डीलरों को अंगूठा लगाने पर राशन मिलेगा। डेटाबेस कार्य पूर्ण होने पर राशन कार्ड धारक का कोई भी सदस्य डीलर से राशन ले सकता है। क्योंकि राशन कार्ड से लिंक आधार नंबर डालते ही पूरा ब्यौरा दिखेगा। उन्होंने कहाकि राज्य सरकारों से राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने की सिफारिश की गयी है। केंद्र सभी डीलरों को 35 रुपये प्रति कुंतल देय है। साथ ही अब महीने के तीसरे सप्ताह के बीच राशन डीलरों को उनके द्वार पर गेहूं, चावल व अन्य सामान पहुंचेगा, ताकि महीने के पहली तारीख से राशन बंटना शुरू हो जाये।

एनएसआई में प्रशिक्षण केंद्र एवं छात्रावास सह अतिथि गृह का शिलान्यास

कानपुर, 23 जनवरी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सचिव रविकांत ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में प्रशिक्षण केंद्र एवं छात्रावास सह अतिथि गृह की आधारशिला रखी। सचिव के साथ संयुक्त सचिव (शर्करा एवं प्रशासन) सुभाशिष पंडा, संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन भी साथ थे। निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण अनुमानित राशि 3.25 करोड़ में होना है और इसमें 200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। प्रस्तावित छात्रावास में 48 विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं के रहने की व्यवस्था भी होगी।

राष्ट्रीय सहारा 24-01-2018

अब मनचाही दुकान से ले सकेंगे राशन

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

राशन उपभोक्ता जल्दी नही मन मुताबिक किसी भी राशन दुकानदार से सामान ले सकेंगे। मतलब यह कि यदि आपको अपने मोहल्ले के कोटेदार का व्यवहार नहीं पसंद है या वह आपको परेशान करता तो आप बगल के मोहल्ले के कोटेदार के पास जाकर राशन का सामान ले सकते हैं। इससे राशन दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण रोकने में मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में नये छात्रावास व प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण की आधारशिला रखने आये केन्द्रीय सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) रविकांत ने बताया कि उक्त सुविधा राशन कार्डों के डिजिटाइज्ड विवरणों को आधार कार्ड से जोड़ कर मुहैया करायी जायेगी। राशन उफभोक्ताओं को अंगूठे के निशान के सत्यापन व रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर ओटीपी के माध्यम से किसी भी राशन दुकान से सामान लेने की सुविधा मिलेगी। केन्द्रीय सचिव ने बताया कि जन वितरण प्रणाली में सुधार को तेजी से काम चल रहा है। विभिन्न जिलों के राशनकार्डो के विवरण को डिजिटाइज्ड किया जा चुका है। अब प्रदेश भर के राशन कार्ड विवरणों को आपस में मर्ज किया जाना है। इससे कार्डों के डुप्लीकेशन के मामले भी सामने आएंगे व उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या सामने आ सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों की मदद से ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हर माह 30-31 तारीख तक राशन दुकानदारों के द्वारा पर डोर स्टेप डिलीवरी से समस्त सामान पहुंच जाय व 1 से 15 तारीख तक उसका वितरण किया जाय। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार राशन दुकानदारों के कमीशन में वृद्धि के लिए भी प्रयासरत है। राशन दुकानदारों को केन्द्र की ओर से ₹ 35 प्रति कुंतल की दर से कमीशन देय है। इसके अलावा राज्यों से सिफारिश की गयी है कि वह भी अपने साप से राशन दुकानदारों को कुछ कमीशन राशि का भुगतान करे।

श्री रविकांत ने बताया अभी तक शहरी क्षेत्रों के करीब 80 फीसद राशनकार्डों को आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है। प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (पीओएस) के जरिए अंगूठे के निशान के जरिए राशन वितरण की शुरूआत भी करा दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकानों तक सामान पहुंचाने के बाद क्षेत्र के करीब 50 चुनिंदा लोगों को फोन पर उसकी सूचना दी जाती है, ताकि वे राशन वितरण पर नजर रख सकें।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में छात्रावास व सह अतिथि गृह का शिलान्यास करते केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव रविकांत व संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन। फोटो : एसएनबी

केन्द्रीय खाद्य एवं वितरण प्रणाली सचिव ने कहा कि जन वितरण प्रणाली में सुधार को तेजी से हो रहा काम

राशन दुकानदारों को देय मार्जिन मनी बढ़ाने को केन्द्र सरकार ने की राज्यों से राज्यांश देने की सिफारिश

शर्करा संस्थान में केंद्रीय सचिव ने रखी नव-निर्माण की आधारशिला

8.75 करोड़ की लागत से बनेगा प्रशिक्षण केन्द्र एवं छात्रावास सह अतिथि गृह

कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में मंगलवार को रविकांत, सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) भारत सरकार ने 'प्रशिक्षण केन्द्र एवं छात्रावास सह अतिथि गृह' के नवनिर्माण की आधारशिला रखी तथा संस्थान के कार्यकलापों, अनुसंधान व शैक्षिक गतिविधियों की समीक्षा की। सुभाशीष पंडा संयुक्त सचिव (शर्करा एवं प्रशासन) भी उनके साथ आये थे।

उक्त निर्माण पर करीब ₹ 8.75 करोड़ की लागत आनी है। प्रशिक्षण केन्द्र नवीनतम प्रभावी अध्यापन व प्रशिक्षण के लिए आडियो-विजुअल होगा व 200 लोगों के बैठने की क्षमता वाली होगी, जबकि छात्रावास में 50 विद्यार्थियों-प्रशिक्षुओं के रहने की व्यवस्था होगी। संस्थान के निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन ने बताया कि यहां लंबे समय से प्रशिक्षण केन्द्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। श्री रविकांत व सुभाशीष पंडा ने संस्थान की 'विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला' का भी दौरा किया, जिसे हाल में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हुई है। इससे संस्थान शर्करा व चीनी मिलों से प्राप्त अन्य नमूनों का उच्चतर विश्लेषण करके ज्यादा राजस्व कमा सकेगा। उन्होंने संस्थान में जारी नवीनतम अनुसंधान कार्य जैसे बगास से बायो डिटर्जेंट, बगास से खाद्य मशरूम, शर्करा उद्योग के प्रेसमड व अन्य अवशिष्ट पदार्थों से बायो सीएनजी निर्माण, प्रदूषित जल शोधन तकनीकों में रुचि दिखायी। सचिव ने निदेशक को इन सभी तकनीकों को वाणिज्यिक प्रयोग में लाने की सलाह दी। केन्द्रीय सचिव ने शर्करा संस्थान द्वारा शीरे आधारित डिस्टलरीज के लिए विकसित 'एनएसआई/बीसी/114/यीस्ट स्ट्रेन' को भी बिक्री के लिए जारी किया। यह स्ट्रेन खराब गन्ने के जूस से निकाला गया है और शीरे में उपस्थित चीनी को अल्कोहल में बदलता है। इसे बाजार में मौजूद अन्य स्ट्रेनों से बेहतर पाया गया है। निदेशक का कहना है कि इस स्ट्रेन को लेने के लिए कई डिस्टलरी संस्थान से संपर्क कर चुकी है।